लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

MMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Un
Parliament Library Buildi
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २८—सातवां सत्र, १९६४]

अंक ३१—शनिवार, २१ मार्च, १९६४/१ चैत्र, १८८६ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **विषय**	**पृष्ठ**
***अल्प सूचना**	
प्रश्न संख्या	२४१३–१७
१४ भारत और पाकिस्तान के कमाण्डरों की बैठक . .	२४१३–१६
१५ अलीमाटी परियोजना	२४१६–१७
सभा का कार्य	२४१८–१९
गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे मे	२४१९–२०
अनुदानों की मांगें	२४१९–४५
प्रतिरक्षा मंत्रालय	
श्री काशीराम गुप्त	२४१९–२०
श्री महताब	२४२१–२२
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती	२४२२–२४
श्री बृज राज सिंह–कोटा	२४२४–२५
श्री हरि विष्णु कामत	२४२५–२८
श्री रिशांग किशिंग	२४२८–२९
श्रीमती शारदा मुकर्जी	२४२९–३०
श्री लहरी सिंह . . .	२४३०–३२
श्री बाकर अली मिर्जा	२४३२–३३
श्री गजराज सिह राव	२४३३–३४
डा० मा० श्री अणे	२४३४
श्री हेम राज	२४३४–३६
श्री मा० ल० जाधव	२४३६–३७
श्री अ० व० राघवन	२४३७
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह	२४३८

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXVIII—Seventh Session, 1964]

No. 31--Saturday, March 21, 1964/Chaitra 1, 1886 (Saka)

Subject	PAGE
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	2423.17
*Short Notice Question No.	
14 Indo-Pakistan Commanders Meeting . .	2413–16
15 Alimati Project.	2416–17
Business of the House	2418 19
Re : Statement by Minister of Home Affairs	2419–20
Demands for Grants	2419–45
Ministry of Defence	
Shri Kashi Ram Gupta	2419–20
Shri Mahatab	2421–22
Shri Siddhanti	2422–24
Shri Brij Raj Singh-Kotah	2424–25
Shri Hari Vishnu Kamath	2425–28
Shri Rishang Keishing	2428–29
Shrimati Sharda Mukerjee . . .	2429–30
Shri Lahri Singh	2430–32
Shri Bakar Ali Mirza	2432–33
Shri Gajraj Singh Rao	2433–34
Dr. M. S. Aney	2434
Shri Hem Raj	2434–36
Shri M. L. Jadhav	2436–37
Shri A. V. Raghavan	2437
Shri Birendra Bahadur Singh	2438

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें—जारी	
श्री० राम मनोहर लोहिया . . .	२४३८–४०
श्री लीलाधर कटकी	२४४०–४१
श्री फ्रेंक एन्थनी	२४४१–४३
श्री कृष्णपाल सिंह	२४४३–४४
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२४४४
श्री यशपाल सिंह	२४४४–४५
श्री यशवन्त राव चव्हाण	२४४५

Subject	PAGE
Demands for Grants—*contd.*	
Dr. Ram Manohar Lohia	2438-40
Shri Liladhar Kotoki	2440-41
Shri Frank Anthony	2441-43
Shri Krishnapal Singh	2443-44
Shri U. M. Trivedi	2444
Shri Yashpal Singh	2444-45
Shri Y. B. Chavan	2445

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, २१ मार्च, १९६४/१ चैत्र, १८८६ (शक)

Saturday, March 21, 1964/Chaitra 1, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

भारत और पाकिस्तान के कमाण्डरों की बैठक

\+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४.
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान जम्मू सियालकोट सीमा पर भारत और पाकिस्तान के कमाण्डरों की बैठक करने के राष्ट्र संघ के मुख्य सैनिक प्रेक्षक के सुझाव से सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक की कार्यविलि क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने युद्ध विराम को स्थायी बनाने के लिए इस द्वि-पक्षीय बैठक के विचार के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव रखा था ; और

(घ) क्या रामगढ़ क्षेत्र में अब गोली चलाना बन्द हो गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में कच्छिस्तान क्षेत्र में युद्ध विराम की व्यवस्था करने तथा दोनों पक्षों के सशस्त्र सैनिकों को हटाने पर विचार किया गया था।

(ग) चूंकि यह बैठक कमाण्डरों के स्तर पर हुई थी, अतः भारत सरकार ने कोई भी प्रस्ताव नहीं रखे।

(घ) ११ मार्च, १९६४ से इस क्षेत्र में गोली चलाये जाने की कोई घटना नहीं हुई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि २५ मार्च को ब्रिगेडियर स्तर पर एक और बैठक करने का विचार हैं ? यदि हां, तो इस बैठक की कार्यावलि क्या होगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वे सामान्य रूप से १७ तारीख के कार्यवृत्त अथवा समझौते में वर्णित निर्णयों की क्रियान्विति के बारे में विचार-विमर्श करेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : ब्रिगेडियर स्तर की बैठक में जिस विसैन्यीकरण योजना पर विचार किया गया तथा जिसको अन्तिम रूप दिया गया, उसका क्या ब्योरा है तथा राष्ट्र संघ के प्रेक्षक किस प्रकार इस बात का सत्यापन करेंगे कि विसैन्यीकरण योजना को कार्य रूप दिया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कार्यवृत्त से पता चलता है कि यह निर्णय किया गया था कि सेना के पीछे हटाने का कार्य तीन चरणों में पूरा होना चाहिये। **प्रथम चरण** : १९ मार्च को दोपहर के १२ बजे तक अग्रिम खाइयों को खाली करना तथा उनको पाट देना और प्रतिरक्षा हेतु बनाये गये समस्त अन्य साधनों को नष्ट करना देना ? **द्वितीय चरण** : २० मार्च को प्रातः ८ बजे तक दोनों ओर सबंधित अग्रिम खाइयों के मध्य से ५०० गज की दूरी तक समस्त खाइयों को खाली करना तथा उनको पाटना और प्रतिरक्षा के हेत निर्मित साधनों को समाप्त करना और **तृतीय चरण** : २१ मार्च को प्रातः ८ बजे तक इस सामान्य क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर लगभग ४ से ६ मील के अन्दर समस्त सैनिक पड़ावों को खाली करना तथा प्रतिरक्षा हेतु निर्मित साधनों तथा भारी हथियारों को हटा लेना।

श्री हेम बरुआ : बहुत विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हमारी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान उन शस्त्रास्त्रों का युद्ध विराम रेखा के पास प्रयोग कर रहा है जो उसको अमरीका ने दिये हैं। दूसरी ओर, माननीय प्रधान् मंत्री जी ने इस सभा में हमें यह आश्वासन दिया था कि अमरीका ने अपने भारत स्थित राजदूत द्वारा यह आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को दिये गये शस्त्रास्त्रों का कभी भी भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा हमारी सरकार का इस मामले में क्या करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तानी प्रतिरक्षा सैनिकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले शस्त्रास्त्र अमरीका के बने हुए हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या माननीय प्रतिरक्षा मंत्री इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास कुछ जानकारी है, तो वे उसको दे सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरे पास जो जानकारी है वह अत्यन्त विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त की गई है।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मैंने उनको ठीक प्रकार से सुना है तो, उन्होंने कहा कि यह कमाण्डरों की बैठक थी और इसीलिये सरकार ने किसी प्रकार के अनुदेश अथवा प्रस्ताव नहीं रखे । चूंकि यह मामला युद्ध विराम रेखा से संबंध रखता है, जिसका कि दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रीय महत्व हो गया है, अतः क्या सरकार का यह विचार है कि युद्ध विराम रेखा के समुचित पालन करने के इस महत्वपूर्ण मामले को, जो कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक मामला है, कमाण्डरों अथवा ब्रिगेडियर के बैठक के बाद सरकारी स्तर पर उठाया जाय ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों की सहायता से वहां पर स्थायी रूप से शांति स्थापित की जा सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से इस मामले को सरकारी स्तर पर उठाना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसा करने का अर्थ यह होगा कि हम स्वयं ही इस प्रश्न को एक विवाद के रूप में पुनः खड़ा कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री जी का ध्यान 'स्टेट्समैन' तथा अन्य समाचारपत्रों में प्रकाशित आज के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस कब्रिस्तान में एक गोला रखा पाया गया जिसके फट जाने के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रेक्षक गंभीर रूप से घायल हो गये ? यदि हां, तो क्या उनको इस बात की कोई जानकारी है कि एक ओर तो पाकिस्तान बातचीत करने का आयोजित प्रयास कर रहा है तथा दूसरी ओर अधिक गड़बड़ पैदा करने की तैयारी कर रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस मामले में जो जानकारी मुझे है वह यह है कि पाकिस्तान के विंग कमाण्डर कोई मेजर का पांव गोले पर पड़ गया था जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा राष्ट्र संघ के दो प्रेक्षक भी जख्मी हो गये ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह गोला किसने रखा ? क्या यह पाकिस्तानी कर्मचारियों द्वारा रखा गया ?

अध्यक्ष महोदय : अवश्य किसी पाकिस्तानी ने ही रखा होगा।

Shri Bade : The answer just now given by the hon. Minister relates to this grave-yard area. Would the question of giving effect to similar cease-fire arrangements and disengagement of armed personnel in the remaining area also be considered ?

Mr. Speaker : This question is about that particular grave-yard area.

श्री दाजी : कुछ समय पहिले यह मामला राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया था। क्या इस विशेष पहलू का भी निर्देशन किया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रेक्षकों ने प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय राज्यक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश किया ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया गया है।

श्री रंगा : क्या राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि इस बात को भली भांति सुनिश्चित करने के लिये कि दोनों ओर के क्षेत्रों में ५ या ६ मील के दायरे में किसी भी प्रकार के शस्त्रास्त्र न हों, दोनों ओर के कमाण्डरों को एक दूसरे के क्षेत्र का निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिये ताकि वे अपनी अपनी सरकारों तथा राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को इस बात की संतुष्टि दिला सकें कि इस समझौते का ठीक प्रकार से पालन किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : स्थिति यह है कि दोनों ओर लगभग १०० वर्ग मील का यह क्षेत्र सैनिकों द्वारा खाली कर दिया जायेगा परन्तु सीमा के उनके क्षेत्र मे पाकिस्तानी रेंजरों की तथा हमारे क्षेत्र में पुलिस की दो दो टुकड़ियां रहेंगी। स्वभावतः, पुलिस की टुकड़ियां आपस में सम्पर्क बनाये रखेंगी। निश्चय ही हम उनको अपने क्षेत्र में नहीं आने देंगे तथा हम भी उन के क्षेत्र में नहीं जायेंगे। इस बात को सुनिश्चित करने का काम राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों का होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि कमांडरों की बैठक के एक दिन बाद ही १८ तारीख की रात्रि को तीन पाकिस्तानी हमलावरों ने भारतीय गश्ती टुकड़ी पर गोली चलायी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, हां।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि बैठक में तीन क्रमबद्ध निर्णय क्रिये गये थे जिनमें से प्रथम निर्णय का १२ घंटे के अन्दर, दूसरे का अगले ८ घंटे के अन्दर तथा तीसरे का आज पालन किया जाना था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की कोई सूचना प्राप्त हुई है कि इन निर्णयों को कार्य रूप दिया गया है अथवा नहीं और क्या २१ तारीख को कार्य रूप दिये जाने वाले निर्णय को आज या किसी अन्य दिन कार्य रूप दिया जायेगा?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे यह जानकारी है कि प्रथम दो चरण पूरे हो चुके हैं तथा तीसरा पूरा किया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस बैठक में पाकिस्तानियों द्वारा युद्धविराम रेखा के बार बार तथा जानबूझकर उल्लंघन किये जाने की बात भी उठाई गई थी और क्या बैठक में यह निर्णय किया गया था कि तीन चरणों मे पूरे होने वाले कार्यक्रम की क्रियान्विति का प्रभावशाली ढंग से सत्यापन करने के लिये राष्ट्रसंघ के प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, नहीं। यह बैठक तो केवल कब्रिस्तान क्षेत्र सम्बन्धी सामान्य प्रश्न पर विचार करने के लिये हुई थी।

अलीमाटी परियोजना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५. श्री रा० गि० दुबे : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक १९ मार्च, १९६४ के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मैसूर राज्य के बीजापुर नगर मे बिल्कुल हड़ताल रही और बीजापुर नगरवासियों ने सामूहिक भूख हड़ताल की;

(ख) क्या यह सच है कि इस आन्दोलन का कारण यह है कि बीजापुर के अकाल के क्षेत्रों के लाभ के लिये बनायी जाने वाली अलीमाटी परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है ; और

(ग) क्या यह सच है कि बीजापुर के अकाल के क्षेत्रों के लिये अलीमाटी ही एक मात्र परियोजना है जो सैकड़ों वर्षों से अकाल से हानि उठाने वाले इन क्षेत्रों को लाभ पहुंचा सकती है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) मैसूर सरकार द्वारा भेजी गई मूल अपर कृष्णा परियोजना, प्रथम चरण, मे यह सुझाव था कि अलीमाटी में बांध को इसकी पूरी ऊंचाई तक तथा नारायणपुर बांध को आंशिक ऊंचाई तक बनाया जाय। नहर से बीजापुर तथा गुलबर्गा दोनों जिलों को पानी दिया जाना था। जांच के परिणामस्वरूप, अपने उपलब्ध संसाधन का सर्वोत्तम लाभ उठाने तथा शीघ्र फल प्राप्त करने की दृष्टि से इस चरण में रूपभेद किया गया है। तथापि, अब मंजूर की गई योजना में अगले चरण में बनाये जाने वाले बांध के लिये अलीमाटी में नींव सम्बन्धी कार्य की व्यवस्था है। परन्तु बीजापुर के निवासी यह चाहते हैं कि अलीमाटी बांध का निर्माण अभी चालू कर दिया जाना चाहिये ताकि बीजापुर के क्षेत्रों को प्रथम चरण में ही सिंचाई के लिये पानी प्राप्त हो सके। सम्भवतया, यह आन्दोलन बीजापुर के निवासियों के इस असंतोष के कारण हुआ है।

(ग) जी हां, जैसी कि इस समय योजना बनाई गई है।

श्री रा० गि० दुबे : क्या यह सच है कि मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार बीजापुर जिले के काफी क्षेत्रों को लाभ पहुंचना था और यदि हां, तो कितना?

डा० कु० ल० राव : जी, हां। इसमें बीजापुर जिले की डेढ़ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था थी।

श्री रा० गि० दुबे : चूंकि मंत्री जी इस बात से सहमत है कि बीजापुर बहुत पहिले से एक अकालग्रस्त क्षेत्र है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसके साथ साथ बीजापुर जिले में भी सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये उनका क्या मुख्य कदम उठाने का विचार है?

डा० कु० ल० राव : बीजापुर जिले में प्रथम चरण में ही सिंचाई की व्यवस्था किये जाने के बारे में गत कुछ दिनों में तथा पहिले भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसीलिये, मेरा अप्रैल, १९६४ में इन क्षेत्रों का दौरा करने का विचार है।

श्री बासप्पा : मंत्री जी कहते हैं कि बीजापुर एक अकालग्रस्त क्षेत्र है। क्या मैं जान सकता हूं कि नारायणपुर बांध के बन जाने पर बीजापुर जिले के कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी? और यदि इसके स्थान पर अलीमाटी परियोजना पूरी हो जाये, तब इसके कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी? यदि अलीमाटी परियोजना के पूरा होने से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना को पूरा करने में बाधा क्यों है?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि इस समय मंजूर किया गया है, यदि नारायणपुर बांध को पूरा किया जाय तो बीजापुर जिले के किसी भी क्षेत्र की सिंचाई नहीं होगी।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंहा) : मुझे २३ मार्च को आरम्भ होने वाले आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की ोषणा करनी है, जो इस प्रकार होगा:—

(१) प्रतिरक्षा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान।

(२) निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान—:

परिवहन

विधि

डाक तथा तार

खाद्य तथा कृषि

सिंचाई और विद्युत्

सम्भरण तथा प्रविधिक विकास।

मुझे सभा को यह और सूचित करना है कि हम पहले ही निर्धारित समय से ४ घंटे पीछे हैं। या तो सभा अधिक समय तक बैठे जो कि सम्भव नहीं है, चुंकि ५ बजे के पश्चात सभा में गणपूर्ति नहीं होती, या फिर कुछ मांगों के लिये नियत समय में कमी करनी होगी, या आखिरी मांग के सिलसिले में मुखबन्ध का प्रयोग करना पड़ेगा।

श्री रंगा (चित्तूर): राउरकेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के मरने की खबरें मिली हैं, इसलिये बेहतर है कि माननीय मंत्री इस बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन अब दे दें और वक्तव्य कल दे दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से कहूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रतिरक्षा मंत्रालय संबंधी मांगों पर चर्चा के लिये १० की बजाय १२ घंटे का समय दिया जाना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सभा में गणपूर्ति संबंधी कठिनाई की दृष्टि से सभा की बैठक का समय १०.३० से १-३० अथवा १ बजे तक हो और अन्तरावधि उस के पश्चात् हो।

अध्यक्ष महोदय : यदि अन्य दलों के नेता एवं संसद्-कार्य मंत्री सहमत हों, तो मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। इस प्रकार से इस बारे में निर्णय लेना कठिन है।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि सभा में गणपूर्ति बनाये रखें, इसलिये उन का यह कथन, कि ५ बजे के पश्चात गणपूर्ति नहीं होती, अनुचित है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरा सुझाव है कि सभी मदों पर चर्चा के लिये एक समान ही समय नियत न कर के कुछ मदों के लिये अधिक समय नियत किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव इस समय नहीं दिया जा सकता ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I request that those, whose sons were put to death in NEFA, and also who remain present in the House all the time, should be given an opportunity to say something on the Demands for Defence Ministry.

Mr. Speaker : Such a complaint should be made to the concerned leader of the party and not to me.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : We have not yet received the reports of all the Ministries, and secondly, the Calling Attention Notice, regarding law and order situation in the country, should be admitted.

Mr. Speaker : The business in hand at present is statement regarding Government Business. Questions can be asked only regarding it.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Speaker, you should do justice with us by giving us sometime to speak. Why do you leave us at the mercy of our leaders ? **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : यह झगड़ा आप के और आप के नेता के बीच का है, जिस में मैं कुछ नहीं कर सकता ।

गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में

Re STATEMENT BY MINISTER OF HOME AFFAIRS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कृपया आप मंत्री महोदय से कहें कि वह राउरकेला की स्थिति के बारे में वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : वह कल एक वक्तव्य दे रहे हैं । आज वह वक्तव्य दे सकते हैं कि नहीं इस बारे में मैं उन से पूछूंगा ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

प्रतिरक्षा मंत्रालय —जारी

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : In army affairs we have to work carefully and in a planned way, otherwise the consequences will be grave. Recently, at a closing ceremony of the junior N.C.C., at Lt. Colonel was to preside. But he did not come and a lady presided instead. The proceedings of that

ceremony could not go on smoothly, so much so that they forgot to sing the National Anthem. This clearly shows that we do not try to remove the weaknesses of the Democratic system.

Corruption is prevalent in the purchase departments. Crores of rupees can be saved by avoiding wasteful expenditure. Tendency to interfere in the administrative affairs is found even in the Army. These allegations are based upon my personal experience.

The situation in Kashmir is very explosive. The members of the Action Committee are there in the Plebiscite Front. National Conference is divided in many camps. At the same time when Kashmir issue is raised in the Security Council, demonstrations are held at Srinagar. It seems poeple there are doing things in collusion with Pakistan. Therefore the situation there should be tackled immediately.

Shri Raghunath Singh has asked the Muslim infiltrants to be more coutious. But the responsibility for checking infiltration is primarily of the Government who accepted the division of the country. Therefore, the note of caution should have been directed towards the Government. Checking of infiltration as also clearing Assam and Tripura of the Pakistan infiltrants, is closely associated with security of the State. Home Guards should be posted there to keep a strict watch on the activities of such people.

We should make it clear to America and Pakistan that if they are earnest about helping us, they should ask Pakistan to vacate our territory.

Our greatest internal weakness is that there is no opposition party which could take over the responsibility of governing the nation from Congress. My suggestion is that Lok Sabha election be held six month ahead of scheduled time and elections to legislative bodies be held six months behind the scheduled time. If this suggestion is accepted there definitely will emerge a single powerful party.

We must maintain the secular character of our state. It is correct that we should not try to appease the minoritries, but at the same time we must stick to the secular principle, otherwise the communal feelings are bound to wreck our country's future.

A ten-year plan should be formulated about our country's defence. The Government may raise any amount of tax for that plan, but once that plan is executed, our country should be competent to face any danger.

गृह-कार्य मंत्रीके वक्तव्य के बारे में--जारी

RE: STATEMENT BY MINISTER OF HOME AFFAIRS—*Contd*.

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह आज वक्तव्य दे सकेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : सोमवार को मैं इस घटना संबंधी ब्योरेवार एक वक्तव्य दूंगा ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

प्रतिरक्षा मंत्रालय —जारी

श्री महताब (अंगुल) : मैं चाहता हूं कि हमारे देश का प्रतिरक्षा-निर्माण स्थायी आधार पर हो, इसलिये मैं कुछ सुझाव दूंगा । चीनी आक्रमण के समय हमें हार हुई और उस के लिये एक कारण यह बताया गया कि हम तैयार नहीं थे और तैयार इसलिये नहीं थे कि हमारे देश में विदेशियों ने शताब्दियों से कुछ ऐसी परम्परायें बनाईं । उन्होंने देश का नैतिक पतन कर दिया । यहां तक कि लोग प्रतिरक्षा तथा युद्ध की बात सोच भी नहीं सकते थे । शस्त्रास्त्र अधिनियम इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने बनाया था । फिर, उन्होंने युद्ध के लिये कुछ ही जातियों को तैयार किया । जब चीनी आक्रमण हुआ तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ कदम उठाये गये । होम गार्ड बनाये गये, प्रादेशिक सेना का विस्तार हुआ, सीमांत गार्ड बनाये गये और राष्ट्रीय छात्र-सेना दल का भी विस्तार किया गया परन्तु जब तक हम जनता और प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा में सम्बन्ध स्थापित नहीं करेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । यह जितने भी संगठनों की चर्चा मैं ने की यह सब प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत होने चाहिएं ।

सीमांत धावों का मुकाबला करने के लिये सीमांत गार्ड होने चाहिएं । और जनता को शस्त्रास्त्रों के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

देश की सुरक्षा की बात जब कभी होती है तो यह कहा जाता है कि सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकारों का है । परन्तु इस धारणा को हमें ठीक करना है । अभी कल ही श्रीमती चक्रवर्ती कह रही थीं कि हैलीकाप्टर सीमांत क्षेत्र में कैसे उतर गया । वास्तव में सीमांत क्षेत्रों में जो पुलिस कर्मचारी हैं वह सुरक्षा संबंधी काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते । आवश्यकता इस बात की है कि यह कार्य सेना के सुपुर्द किया जाय और प्रतिरक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व हो । काश्मीर की सीमा पर भी सुरक्षा का कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन होना चाहिए और वह कार्य होम गार्डों और सीमांत गार्डों के जरिये किया जाय । अंग्रेजों के काल में भी सीमांत अभिकरणों का काम सेना के अन्तर्गत होता था । अब भी वैसे ही होना चाहिए ।

अब मैं सैनिक गुप्तचर विभाग के बारे में कहूंगा । पहले जहां कहीं एक स्थिति पैदा होती थी तो इस विभाग वाले स्थिति का अध्ययन कर के अपना प्रतिवेदन किया करते थे और फिर उस पर कार्यवाही की जाती थी । परन्तु अब या तो प्रतिवेदन उन के द्वारा किया ही नहीं जाता या उस पर अमल नहीं किया जाता । मेरा अनुरोध है कि यदि आप निहत्थे लोगों के लिये सेना का प्रयोग करते रहेंगे तो सेना का नैतिक पतन हो जायगा । सेना का प्रयोग केवल सशस्त्र लोगों के मुकाबले में होना चाहिए ।

एक अन्य गलती हम करते रहे हैं । सेना को बेकार समझ कर हम ने इस का प्रयोग मकानों के निर्माण आदि कार्यों के लिये किया, जिस पर कुछ सेना अधिकारियों ने असन्तोष प्रकट किया । हमें चाहिए कि सेना से केवल देश की रक्षा संबंधी काम कराया जाय ।

देश की आन्तरिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा का गुप्तचर कार्यों से घनिष्ट संबंध है। कलकत्ता में यदि हमारा गुप्तचर कार्य अधिक कुशलता पूर्वक होता तो स्थिति का सामना अच्छी तरह से किया जा सकता था। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि गुटतचर कार्यों में अधिक कुशलता लाई जाय।

इस के अतिरिक्त बहुधा मंत्रियों को मजबूर किया जाता है कि वह किन्हीं सुरक्षा मामलों के बारे में सूचना दें। प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी मामलों के बारे में मंत्रियों को सूचना नहीं देनी चाहिए। यदि वह सही सूचना देते हैं तब भी उचित नहीं होता और यदि गलत सूचना देते हैं तब भी हानि होती है।

सेना पदाधिकारियों और अन्य सैनिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिएं जो आज नहीं पाये जाते। पदाधिकारियों का अन्य सैनिकों के साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए।

सर फ्रांसेस टकर ने अपनी पुस्तक "व्हाईल मेमोरी सर्व्स" में हमारी कई एक कुरीतियों एवं त्रुटियों की चर्चा की। उस की आलोचना को छोड़ कर, उस ने जो त्रुटियें बताई हैं उन्हें दूर करने की चेष्टा की जानी चाहिए।

प्रतिरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से एक निश्चित नीति का अनुसरण होना चाहिए। हमारी नीति निरन्तर एक होनी चाहिए। बार बार इस में परिवर्तन नहीं होने चाहिएं।

हमारी सेना ने प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। परन्तु अब कहा जाता है कि हमारी सेना ब्रिटिश जनरलों के अधीन ही अच्छी तरह काम कर सकी थी। इस धारणा को हमें बदलना है और इस प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि हम सेना की प्रतिष्ठा बढ़ायें, उन का आदर करें। सेना की कुशलता तभी बढ़ सकती है जब उस का सम्मान किया जाय।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : The Army is like a soul in a body. If our Army is strong, no danger can affect our nation. Our primary need is the streng thening of the Army, which can hardly be effected by speeches and loud words. I feel our army is worthy of a very creditable performance, but our politicians fail to realise this fact. Good politicians sometrmes fail to be good soldiers. But for the interferenrce of politicians, a part of Kashmir would not have been under the illegal occupation of Pakistan. Even the exodus of minorities from East Pakistan, and their rehabilitation has become a collossal problem for us. The main reason is that our actions are mainly defensive in nature. If we want to check Pakistan from taking aggressive measures, we will have to resort to actions of offensive character. We have to inculcate the habit of being firm, and from that point of view to strengthen our Army. In order to strengthen our Army we should be prepared to spend any amounts of money. We have to learn from our past mistakes. We have lost Burma, Ceylon and even Tibet by our wrongful and weak policy.

Pakistan should be made to part with her territory, where the minorities pushed out by her could be rehabilitated. Our Government is not prepared to ask Pakistan for that territory, because it lacks confidence in itself.

Defence of our country, as has been pointed out in the Report is closely associated with our foreign policy. Vast areas of our territory have been illegally occupied by our enemies, but we are unable to take any action. Our foreign policy is weak. Our policy of non-alignment has failed and it has become a fine joke. Only a very strong nation can afford to be non-aligned. Our Government cannot defend this country by letters of protest an dby holding enquiries.

The second criteria for a soldier is to be alert and active in defence of the country. But our Government do not give them freedom to show their feats nor due honour is shown to them. To cite an example a soldier who was defending a post against the Chinese in NEFA and who had asked for reinforcement was made to retreat by an order on telephone given from the centre. He laid his life in defence of the country but the Commanding Officer saved his own face by reporting that his performance was not good.

Our Commanders should be given full power to inflict efficiency in their commands. The Defence Department should be under the charge of some military General as he is in better position to know as to where to move the army and how to deal with the hostile nation.

The army personnel should be empowered to make strategic decisions as and when the necessity arises. The imminent fall of Chushule was averted by a timely decision of the pilot to supply the provision to that particular post despite the orders issued to him from here on telephone. Chushule would have fallen to the enemies if those orders were observed. The aimy should be given the power to crush the enemy. The politics should not stand in the way.

For countering the intrigue and conspiracy of the enemy one has to adopt some tactics. The enemy can only understand the language of trigger. Fair deal, negotiations and cooperation with the enemy would do no good worth the name.

The military should be expanded and means of livelihood should be provided for reserved force. Arms should be given to those who can operate them.

The Government has not yet been able to over power the dacoits operating in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan mainly due to fact that they have not been able to evolve any clear cut or firm policy. They should be awarded proper punishment and no concession in this respect should be given to them as being proposed by the Government at present.

70 per cent of the recruitment to the commissioned rank should be made by promotion from Junior officers. The personnel recruited directly to the commissioned post should be made to serve in the ranks at least for five years.

Casteism should not be allowed to flourish in the armv, nevertheless this fact can not be overlooked that the marshall races can give you the best of the soldiers. A regiment with the nomenclature should be formed alongside with the Rajput, Dorgra and Marhatta regiments now existent, as they have shown indescribable feats of valour and bravery in recent fighting in Laddakh area.

174 (Ai)LSD--2.

the army should not to shown in disrespect Sending of our troops to foreign countries should be discontinued.

The secret code should not be in possession of any officer below the rank of Brigadier.

Our ordnance factories should be prevented from the reach of the spies. The anti-national elements who are engaged in sabotaging the country should also be suppressed.

Vir Chakra should be awarded to those who have actually shown valour in the field. No discrimination based on recommendations should be made in this respect.

The first and foremost tasks is to change the thinking of the nation. Once our territory extended from Caspian Sea in the West to Indonesia in the East. We should try to consolidate and solidify our territory and let the other opportunist nations like Pakistan, U.K. and U.S.A. understand that India is in hold of an invincible army.

श्री ब्रजराज सिंह--कोटा (झालावाड़) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

वर्तमान परिस्थितियों में विमान शक्ति का महत्व अत्यधिक है । हर्ष कि बात है कि प्रतिवेदन के पृष्ठ ४६ में वायु बल के आधुनिककरण के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है । हमें स्वतंत्र रूप से अपनी विमान शक्ति को विकसित करना है जो न पूर्व पर आश्रित हो और न पश्चिम पर । इसके लिये हमें जहां से भी उपलब्ध हो सामान खरीदना होगा । हमें ऐसी विमान शक्ति बनानी है जो हमारे देश की रक्षा करने में समर्थ हो । हमारा सामना चीन से है जिसका वायु बल दुनियां में तीसरे दर्जे पर है ।

इस समय हमारे वायु बल की क्षमता प्रतिरक्षा दृष्टि से ही बढ़ाई जा रही है । किन्तु दुनियां में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये निरोधात्मक शक्ति की भी आवश्यकता है अर्थात् हमारी शक्ति केवल ऐसी न हो कि हम शत्रु के विमानों का पता लगा सकें और उनके आक्रमण का सामना कर सकें अपितु ऐसी भी होनी चाहियें कि आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण कर सकें ।

हमारे उद्योग प्रधान क्षेत्रों से और देश के मध्य भाग से तिब्बत तक की उड़ान कुल २० मिनट की है किन्तु यदि हम सम्भावित आक्रमणकारी पर उलट कर आक्रमण करना चाहें तो पता चलेगा कि चीन के उद्योग प्रधान और आर्थिक क्षेत्र यहां से २५०० मील की दूरी पर बसे हुये हैं । हमारा उत्तरी सीमांत २००० मील लंबा है और आक्रमणकारी कहीं से भी आकर आक्रमण कर सकता है । अतः ऐसी पद्धति की आवश्यकता है जिससे हम दूर से ही आक्रमणकारी जहाजों का पता लगा सकें । हमारे रडार 'एयर-बोर्न' होने चाहियें जिससे हम पहाड़ों के उस ओर होने वाली घटनाओं का पता लगा सकें ।

मैं भी शिक्षा अभ्यास देखने गया था । मुझे बताया गया कि हमारी रडार पद्धति में अब भी ऐसी कमियां हैं जिसके कारण संदेश आने में विलम्ब हो जाता है । इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाये ।

आक्रमणकारी विमानों का पता लगाने के साथ ही उन्हें रोकने का भी प्रश्न है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमें आवाज से भी अधिक तेज चलने वाले जहाजों की आवश्यकता है। किन्तु हमें ऐसे जहाजों की भी आवश्यकता होगी जो सब प्रकार के मौसम में लड़ सकें। हमने एम० आई० जी—२१ और एच० एफ० २४ जहाज तैयार किये हैं किन्तु अभी ये जहाज हमारे विमान बल में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

हमें प्रक्षेपणास्त्रों की भी आवश्यकता है। मुझे हर्ष है कि एम० आई० जी०–२१ के साथ उनका निर्माण भी हो रहा है अथवा किया जा रहा है।

हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सेना की सहायता के लिये यौधक विमान हों चाहे वे सुपर-सोनिक हों या दूसरे जो पहाड़ों को पार कर सकें।

मुझे हर्ष है कि हम एलौरी और एम० आई० ४ हेली कोप्टर का निर्माण करने जा रहे हैं। यह सेना को सामान भेजने और घायलों को हटाने आदि के लिये बहुत आवश्यक हैं।

हमारे वायुबल के जहाज लादने वाले बेड़े को भी केरिब्यू और पैकेट जहाजों के द्वारा और सबल बना दिया गया है।

भारी सामान ढोने के काम के संबन्ध में अमरीका द्वारा प्राप्त सी १३० विमानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब ए० एन० १२ विमान भी इस बेड़े में जोड़ दिये गये हैं।

एक ऐसे छोटे जहाज की भी आवश्यकता है जो सीधी युद्ध क्षेत्र तक जा सके। इसके लिये पिलेटस पोर्टर बहुत अच्छा रहेगा।

कानपुर एयरक्राफ्ट डिपो में कुल ४ या ५ जहाज बनाये गये हैं। इसके काम में तेजी लाई जानी चाहिये।

विमान दुर्घटनायें आम हो गई हैं। इनके बारे में सूक्ष्म जांच की जानी चाहिये, प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा कही गई इस बात के बारे में भी जांच की जानी चाहिये कि सीमा के पार पाकिस्तान का एक रेडियो बीकन काम कर रहा है जो हमारे जहाजों को गलत मार्ग प्रदर्शन करता है। इस बात की जांच की जाये कि इन दुर्घटनाओं का कारण संयोग ही है अथवा कुछ और।

प्रतिरक्षा नीति दृढ़ नहीं होनी चाहिये। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किये जाने चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं डा० हरे कृष्ण मेहताब के भाषण सुन रहा था उन्होंने ठीक ही कहा था कि सैनिक जासूसी विभाग में त्रुटियां हैं जिनका पता चीनी आक्रमण के बाद ही हमें लगा है। बामडीला या सेला में एक चाय की दुकान का चीनी मालिक हमारे भेद चीन को बताता रहा है।

आज हमारे सिद्धांतहीन शत्रु पड़ौसी घात लगाये बैठे हैं और हमने अभी १९६२ के अपमान का बदला भी नहीं लिया। ऐसी हालत में हर व्यक्ति यही पूछता है कि क्या हमारी प्रतिरक्षा की व्यवस्था अच्छी है।

प्रतिरक्षा मंत्री ने गत सितम्बर में बताया था कि नेफा में हमारी हार का क्या कारण था। अर्थात् जासूसी, नेतृत्व, कमान, सड़कें और परिस्थिति अनुकूलता सभी का प्रभाव था। उस पर भी भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने हार्दिक खेद नहीं प्रकट किया और मैं आशा करता हूं कि संसद् के देशभक्त लोग उसे पुनः सत्तारूढ़ नहीं होने देंगे।

श्री हेडरसन ब्रूक्स के अपनी रिपोर्ट में सेना की अव्यवस्थित स्थिति का उल्लेख किया है और बताया है कि एक जेनरल को पद त्याग करने के लिए विवश किया गया है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि पिछले चार मास में जितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी जांच से ठीक ठीक कारणों का पता नहीं लगा और जहां तकनीकी विफलता की बात कही गई है वहां भी अन्य कारणों का उल्लेख किया गया है। वे अन्य कारण क्या हैं ?

देश की प्रतिरक्षा के लिए वायुसेना का अत्याधिक महत्व है। अतः मेरा यह निवेदन था कि एक संसदीय आयोग बनाया जाए जिसे तकनीकी और वैमानिक विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो और वह ऐसे मामलों की जांच करे। मैं तो समझता हूं कि यह पाकिस्तानी विध्वंसक कार्यवाहियां भी हो सकती हैं।

चीनी आक्रमण के समय देश के अमीर गरीब सभी लोगों और विशेषतः गरीब लोगों ने इस डावांडोल सरकार को मज़बूत बनाने के लिए अवांछनीय कार्य किया था किन्तु सरकार में दृढ़ निश्चय नहीं है उसमें निष्ठा नहीं है और वह उस बचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं जो उसने चीनियों को देश से निकालने के बारे में दिया था।

प्रतिरक्षा मंत्री ने रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिरक्षा योजना का वैदेशिक नीति से घनिष्ट सम्बन्ध है। इसमें संदेह नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नीति ढीली होती जा रही है और वे चीन के साथ संधि करने वाले है। उन्होंने कहा था कि वे किसी ऐसे सम्मेलन में नहीं जायेंगे जहां चीन का प्रतिनिधित्व होगा किन्तु वे अब बाडुंग सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हैं। प्रतिरक्षा मंत्री इस नीति को स्पष्ट करे। वे अपने परम्परागत साहस का परिचय दें और प्रधान मंत्री को बता दें कि वे हर बात में हां कहने वालों में से नहीं हैं।

भारत की भव्य मूर्ति को कलंकित किया गया है और निरंतर कलंकित किया जा रहा है जब तक कि सरकार की नीति को सुदृढ़ और परिस्थिति अनुकूल नहीं बनायेंगे देश का मुख कलंक से मुक्त नहीं हो सकेगा। आज से तीन हजार वर्ष पहले चाणक्य ने यह बताया था कि शक्तिशाली पड़ौसी बहुत बड़ा शत्रु हैं। चीन ने यह बात प्रामाणित कर दी है। उसने "हिन्दी चीनी भाई भाई" को 'पिन्डी चीनी भाई भाई' में बदल दिया है। इसका परिणाम पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। हमें इस स्थिति को समझना चाहिये।

हमारा यह कर्तव्य है कि जिस किसी देश से भी हमें सहायता मिले उसे बिना किसी झिझक के प्राप्त करें। अरबफोबिया पीड़ित नहीं होना चाहिये जिससे विचलित हो कर हमने इसराइल से सहायता को अस्वीकार कर दिया था। अब अरब के समाचारपत्र भारत से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि भारत सरकार ने जो यहूदी अधिकारियों को क्यों निमुक्त किया है। हमें

अरब देशों को बता देना चाहिये कि उन्हें हमारे देश के कामों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। वे लोग एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा को नहीं समझ सकते।

नौसेना के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि नौसेना भंडार निदेशालय का कार्य सराहनीय है। उसे और प्रयत्न करना चाहिये कि नौसेना की अधिकाधिक वस्तुओं का उत्पादन देश में होने लगे और विदेशी मुद्रा की बचत हो।

प्रतिरक्षा की समस्त सामरिक नीति को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

मनोविज्ञान गवेषणा विभाग को इस बात का भी अध्ययन करना चाहिये कि जवानों और अधिकारियों के सम्बन्ध अधिक अच्छे कैसे बन सकते हैं।

हमें शिवाजी की दुर्ग बनाने की नीति और इसरायल की जहाज नीति को अपनाना चाहिये और सीमा क्षेत्र में किसानों को बसाना चाहिये तथा उन्हें शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करना चाहिये।

सरकार को हिमालय परियोजना को हाथ में ले कर ५०००–८००० फुट की ऊंचाई पर लोगों को बसाना चाहिये।

खेद है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्र में हम निश्चित समय पर सड़क निर्माण पूरा नहीं कर सके। सरकार को यह जांच शीघ्रता से करनी चाहिये।

रिपोर्ट में अनेक प्रकार की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। अतः प्रतिरक्षा मंत्री से यह निवेदन है कि शत्रु से लोहा लेने के अतिरिक्त मंत्रालय के कार्य में भी सुधार करना चाहिये।

संकटकाल में, जब कि अनुभवी सैनिक अधिकारियों की कमी है, यह आवश्यक है कि प्रतिरक्षा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाये जैसा कि असैनिक कर्मचारियों के मामले में किया गया है।

चीन के पास ३००० विमानों का बेड़ा है। सरकार को चीन के खतरे के बारे में सदैव सतर्क रहना चाहिये और अपनी प्रतिरक्षा तैयारी जारी रखना चाहिये। परन्तु प्रतिरक्षा मंत्रालय के आयव्ययक आंकड़े विश्वासोत्पादक नहीं हैं। उन्होंने ५० करोड़ रुपये की राशि लौटा दी है। जनवरी के अन्त तक पिछले वर्ष के अनुदानों में से लगभग ३०० करोड़ रुपये की राशि कम खर्च की गई है। यह बड़ी गम्भीर बात है। यदि इतनी बड़ी राशि बचने की आशा थी तो उन्हें जवानों के वेतन तथा पेंशनें बढ़ा देनी चाहिये थीं। सरकार को जवानों को अधिक वेतन देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये ताकि सेवानिवृत्त होने पर वे अधिक पेंशन के अधिकारी बन सकें।

जवानों और अधिकारियों के बीच भाई चारे के सम्बन्ध होने चाहियें। ब्रिटिश शासनकाल की पुरानी प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये। आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों सम्बन्धी नीति में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। अंग्रेज़ों ने उन में से कुछ को अन्त तक

देशद्रोही माना था और उन्हें उनके वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि नहीं दी गई थी। जब अंग्रेज़ भारत छोड़ कर गये तो उन्होंने उनके वेतन तथा भत्ते ज़ब्त कर लिये थे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। उन्हें उनके बकाया वेतन तथा भत्ते तुरन्त दिये जाने चाहिये।

देश को बाहरी आक्रमण के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिये।

श्री रिशांक किशिंग (बाह्य मनीपुर) : हमारी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की ओर से हर समय खतरा बना हुआ हैं। ये दोनों देश भारत को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इन्होंने हमारे देश पर पहले भी आक्रमण किये हैं और हमारे देश का काफी बड़ा हिस्सा अब भी उनके कब्जे में है। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने इस बारे में काफी कदम उठाये हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय स्थल सेना में ६ पर्वतीय डिवीजनें (माउंटेन डिवीजन) जोड़ दी गई हैं आधुनिक हथियारों का देश में निर्माण किया जा रहा है और सेना की जरूरतें शीघ्र ही पूरी कर दी जायेंगी। वायु सेना को भी सुदृढ़ बना दिया गया है। इन सब बातों के बावजद भी देश की अखंडता तथा स्वाधीनता को बने खतरे का सामना करने के लिए हमें चार अथवा पांच पर्वतीय डिवीजनें और बनानी चाहियें। तभी हम चीन तथा पाकिस्तान के एक साथ हमले का मुकाबला कर सकते हैं। आशा है कि प्रतिरक्षा मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे।

काश्मीर से मिजो जिले तक सारे हिमाचल प्रदेश में स्काउट बटालियन बनाई जायें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

चूंकि इन बटालियनों में स्थानीय व्यक्ति भर्ती किये जाते हैं इसलिये इनको उस इलाके तथा वहां की भाषा की अच्छी जानकारी होती है और वे लोगों का विश्वास भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सेनाओं को भी ये स्काउट दुश्मन के बारे में ठीक जानकारी दे सकेंगे। मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं, जहां शांति स्थापित करने के लिये सेना तैनात की गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां सेना तथा असैनिक अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव है। ऐसी स्थिति में उनका मिलकर काम करना असंभव है जिसके परिणामस्वरूप उस इलाके में राष्ट्रविरोधी तत्वों को दबाने में वे सफल नहीं हो सकते। मुझे आशा है कि स्काउट बटालियनों के बनाये जाने के पश्चात् ये मतभेद दूर हो जायेंगे।

नागालैण्ड तथा मनीपुर में राष्ट्र विरोधी तत्वों के दमन के लिये 'आसाम राइफल्स' तथा 'मनीपुर राइफल्स' जैसे बलों का प्रयोग किया जाना चहिये और वहां पर किसी अन्य राज्य से पुलिस दल नहीं भेजे जाने चाहियें क्यों कि वे वहां के वातावरण से भली भांति परिचित नहीं होते।

"आसाम राइफल्स" को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जाये और उसमें विशेषता प्राप्त अधिकारी रखे जायें क्यों कि उन्हें कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है।

सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य ऐसे अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिये जिसमें राष्ट्रीयता की तथा लगन से काम करने की भावना कूट कूट कर भरी हो ताकि सड़कों के निर्माण के

लिये दिया गया धन समुचित ढंग से खर्च किया जा सके। समूचे सीमन्त क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक सड़कें बनाई जायें तथा रेलवे लाइनों को बढ़ाया जाये।

सेना में जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जाये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं सभा का ध्यान हाल ही में हुई दुखद विमान दुर्घटनाओं की ओर दिलाना चाहती हूं जिसमें स्थल सेना तथा वायु सेना के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी मृत्यु का शिकार हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा यह कर्त्तव्य है कि जहां हम संभव हो सके हम अपने सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करें। भविष्य में अपने जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करके ही हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपना ऋण चुका सकते हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं में यह विश्वास पैदा करना है कि संसद् देश को अन्य नागरिकों के हितों की तरह उनके हितों की भी रक्षा करती है।

गम्भीर विमान दुर्घटनाओं के बारे में इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि हमने एक जांच समिति नियुक्त की थी और उसके ये निष्कर्ष हैं। हमें दुर्घटनाओं के मूल कारण का पता लगाना चाहिये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं में संगठन तथा अनुशासन उच्च स्तर का हो।

१९६२–६३ के प्रतिरक्षा सेवाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिरक्षा व्यय का विस्तार-पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। उसमें केवल प्रत्येक सेवा के लिये निर्धारित धन की राशि दी गई है। सैनिक कर्मचारियों के वेतन, भोजन, कपड़े तथा उनको आवास की सुविधाएं देने पर जो धन खर्च किया गया है और उनकी पेंशन और उपकरणों पर जो धन खर्च किया गया है — इनके बारे में पृथक पृथक आंकड़े संसद् को दिये जाने चाहियें।

प्रतिरक्षा संगठन के बारे में उच्चतम स्तर पर बहुत सी समितियां कार्य कर रही हैं। परन्तु प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि उनके बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाता है और अन्तिम निर्णय कौन करता है। अत : इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। मंत्रिमण्डल की प्रतिरक्षा समिति को प्रतिरक्षा की विभिन्न शाखाओं के कार्यकरण के बारे में हर समय जानकारी रहनी चाहिये क्योंक संकट के समय तुरन्त निर्णय करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह सुनिश्चित करना कि उन निर्णय पर प्रभावी ढंग से अमल किया जायेगा।

अधिकांश आयुध कारखाने (आर्डिनेंस फैक्टरीज़) ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्थापित किये गये थे। यह आश्चर्यजनक बात है कि वही पुरानी पद्धति अब भी चल रही है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि आयुध कारखानों में कुछ सामान्य वस्तुएं बहुत अधिक कीमत पर बनाई जाती हैं जब कि ये वस्तुएं खुले बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। अत : इन्हें खुले बाजार में खरीदने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

कुछ प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों का प्रबन्ध, जिनमें तकनीकी उपकरणों का निर्माण किया जाता है, प्रतिरक्षा सेवा अधिकारियों के हाथ में है जो इस काम के योग्य नहीं हैं। अत : इन कारखानों का प्रबन्ध तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिये।

जहां तक प्रतिरक्षा अनुसंधान, विकास तथा निरीक्षण विभाग का प्रश्न है मैं प्रतिरक्षा मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि क्या इस विभाग को निष्पक्ष रूप से अपनी राय देने की स्वतन्त्रता

है। हमारी बढ़ती हुई सेना तथा सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, एक पृथक सैनिक संभरण मंत्रालय बनाना एक अच्छा कदम होगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय को मेरे इस सुझाव पर विचार करना चाहिये।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि प्रतिरक्षा मंत्री सशस्त्र दलों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले हथियारों का स्तर निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इसके विपरीत हमारी वायु सेना विभिन्न प्रकार के विमानों का प्रयोग करती है। इसके कारण वायु सेना के विमान चालकों तथा तकनीकी कर्मचारियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण बहुत से विमान बेकार पड़े हैं। अतः इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

आजकल के वैज्ञानिक युग में बड़े पैमाने पर युद्ध होना असम्भव है। परन्तु सीमा अतिक्रमण की घटनायें हो सकती हैं अत: देश में तनाव का वातावरण पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने शत्रुओं को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हालांकि हम युद्ध की नीति में विश्वास नहीं रखते फिर भी हम अपने राज्य-क्षेत्र की रक्षा के लिये हर समय लड़ने के लिये तैयार हैं।

हमारी सेनायें कुशल तथा सुसज्जित होनी चाहियें और उनमें गतिविधि की अधिकतम क्षमता होनी चाहिये। अतः सरकार को स्थल सेना की बजाय वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने की नीति अपनानी चाहिये। इसके लिये वायुसेना को आधुनिक वायुयानों, रेडारों आदि से सुसज्जित किया जाना चाहिये। इसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में बनाई गई अनियमित सेनायें प्रतिरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण योग देंगीं। आज के युग में किसी राष्ट्र के लिये स्वतन्त्र युद्ध नीति पर चलना असंभव है। हमें राजनयिक सूत्रों द्वारा विश्व मत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं में उच्च कोटि के युवकों को भर्ती करना चाहिये और अल्प अवधि के (शार्ट सर्विस) कमीशन दे कर लोगों को सेना में नियुक्त नहीं करना चाहिये।

सरकार को सशस्त्र सेनाओं के वेतन, भत्ते तथा पेंशन की दरों का पुनर्विलोकन करना चाहिये ताकि अधिक संख्या में व्यक्ति सेना में भर्ती के लिये आगे आ सकें।

हमारी सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी बड़े देशभक्त तथा परिश्रमी हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों का समर्थन करती हूं।

Shri Lahri Singh (Rohtak) : Taking into consideration the concentration of Chinese forces on the border and the enmity with Pakistan, our defence preparedness has been slow and halting. There is acute shortage of officers particularly technical and medical officers.

Therefore the Government cannot claim that the country can face china and Pakistan squarely. To make up the shortage of techtical officers, the students passing out of technical and medical colleges should be made to serve in the armed forces, because top proiority has to be given to the needs of our defence services. To attract the best talents in the armed forces, 40 per cent posts should be filled from outside and the rest 60 per cent promoted from among the Jawans and J. C. Os. serving in our armed forces. By taking this step, we

shall be able to make up the shortage of army officers and at the same time have the best talents of the country in our armed forces.

If the officer incidentally die and the subordinates are not efficient the army cannot work.

I am not against the recruitment of officers through Emergency Commission. That is essential to fill up the gap. But that should not be the permanent basis. Sixty per cent of the ranks should be promoted to the posts of officers.

We may not concentrate on certain communities for recruitment but such experiments should be made in peace time when N.C.C. training is advanced and our youngmen are more courageous. For the present we must recruit persons from the communities which have marshal traditions. Rajput, Marathas, Jat, Sikhs are reputed for such traditions.

So there is drith of officers and also of the weapons. Our weapons were inferior to those of the Chinese. We should not lag behind in the research for weapons. We must get help from U.K., Germany and Japan for making this research so that they should guide us in manufacturing modern weapons Government does not appear to be serious in this connection. The Government is importing foodgrains from abroad but they are hesitant to import weapons while the democratic countries are sincere to help us so the advance of the Chinese is checkd.

The aircrafts U.S.A. can fly at the speed of 2000 miles an hour and at the height of 70 thousand feet. How our aircrafts can compete those. As regards the manpower China is the biggest power in the world. Though they declare that they are not going to commit aggression on India but they are desirous to creat their supermancy in the whole of Asia by getting a foothold in India. If she sets up a puppet Government in India it becomes very easy for her to have control on the south eastern countries of Asia. Under such circumstances it is essential that we should have agreements with U.S.A. England, Japan and Germany to get help from them.

N.C.C. and territorial army are the second line of defence. In time of need you can recruit persons out of them. But you spend only six crores of rupees on them. The recruits in the territorial army do not get adequate allowances that is why the people are not attracted towards it. The organisation of N.C.C. is also a good step. But its object is not being fulfilled. The training which is given to them is artificial. The N.C.C. cadets must be given advanced training in the modern weapons. Then you can get a number of boys and girls who would be prepared to lay their lives for the country.

Moreover the N.C.C. trainees should be provided with essential literature and high officers and the ministers should visit their training.

The army intelligence is inefficient. The strategy is poor that is why we had to face a defeat at Sela. The reason was obvious that inefficient officers were promoted due to favouritism. We may send for the literature from Russia and U.S.A. and try to learn their technique.

The Welfare fund created for the army men is negligible. Adequate help should be given to the widows of the deceased army men. Formerly the retired army officers were appointed as honorary magistrates but now these posts are occupied by the Congressmen.

The progress of our defence preparation is not adequate. The policy of neutrality and Panchshel has failed. Now if we do not have an alliance with strong nations we will not be able to face the on slaught of Communism.

श्री बाकरअली मिर्जा (वारंगल) : प्रतिरक्षा मंत्रालय ने बड़े ब्योरेवार रिपोर्ट दी है जिसमें पहाड़ीं डिवीजनों विमानों आदि का विस्तृत उल्लेख है। इस पर भी एक सदस्य ने कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ छिपा लिया है।

मैं प्रतिरक्षा मंत्री के कार्य की सराहना करता हूं। उन्होंने सेना में साहस की भावना पुनर्जागरित की है जिसका बहुत महत्व है।

युद्ध सामग्री का उत्पादन १९६१-६२ में ४० करोड़ रुपये का था जो १०० करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। ईशापुर राइफल कारखाने में ऐसी बंदूकें तैयार की जाने लगी हैं जैसी विश्व में कहीं भी नहीं बनती। हम इस पर गर्व कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि कारखाने का नाम नमूना तैयार करने वाले के नाम पर रख देना चाहिये।

हम प्रतिरक्षा मंत्री से और अधिक आशा करते है क्योंकि वे शिवाजी की भूमि के वासी हैं। किन्तु उन्हें जितना पैसा दिया गया था उसमें से बच गया है। यह कारण बताया गया है कि विदेशों से सहायता नहीं मिली। यह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं? फिर इंजीनियरों की भर्ती में क्यों ढीलापन दिखाया गया है जबकि आजका युद्ध मशीनों से लड़ा जाता है।

विमान दुर्घटनाओं के बारे में एक सदस्य ने बताया है कि उनमें से ५० प्रतिशत दुर्घटनाओं का पता नहीं लगा। एक ट्रांसमिटर का अचानक पता लग गया है। संभवत: उसी के कारण ये दुर्घटनाएं हुई हैं। हमारा जासूसी विभाग क्या कर रहा है?

हमें अपनी सेनाओं की प्रतिष्ठा को गिराना नहीं चाहिये। हमारे सैनिक बहुत अनुशासित हैं और देशभक्त हैं।

उनके वेतन भत्तों और पेंशन में कुछ वृद्धि की गई है जिसकी मुझे प्रसन्नता है। उन्हें यह भी अनुभव कराना चाहिये कि यदि हम उन्हें अधिक नहीं दे पाते तो उसका कारण केवल यह है कि यह देश दरिद्र है।

सेना और नौ-सेना में वृद्धि की आवश्यकता है। श्री रघुनाथ सिंह कहते हैं कि अणुशस्त्र लिए जायें। किन्तु हमारे पास इतना असीम धन नहीं कि हम इतनी विस्तृत सीमा की रक्षा के लिए अणु शस्त्र प्राप्त कर सकें। अतः हमें ऐसे शस्त्रास्त्र तैयार करने चाहियें जिनसे हम चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला कर सकें।

जब अमरीका और फ्रांस की सेनाएं और उनका अपार धन वियतनाम और अलजेरिया में कोई प्रभाव नहीं डाल सका तो हम भी चीन और पाकिस्तान का अणुशस्त्रों के बिना भी मुकाबला कर सकते हैं।

इसके लिए यह आवश्यक है कि युद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त देश में एकता पैदा की जाये जो भाषणों से नहीं बल्कि वास्तविक इच्छा से पैदा हो सकती है।

श्री रघुनाथ सिंह ने कहा कि प्रतिरक्षा की बजाय हमें आक्रमण करना चाहिये और मुसलमानों को यह स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि एक भाई यहां हो और एक पाकिस्तान में। यह नीति गलत है। संदेह से एकता पैदा नहीं हो सकती। मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि आप जासूसी के लिए प्राणदण्ड निर्धारित कर दीजिये।

जवान और अधिकारी में अन्तर नहीं होना चाहिये। हमें संयम का जीवन व्यतीत करना चाहिये। उपमंत्री का क्या काम है? उसे इतना वेतन क्यों मिलता है? देश में ६ हजार के करीब संसद् सदस्य और विधायक हैं। यदि वे सब सादगी का जीवन व्यतीत करने लगें तो इतना धन मिल सकता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय खर्च नहीं कर सकेगा।

नेफा के युद्ध ने हमारे साहस को विनष्ट कर दिया है। हमें सशस्त्र सेनाओं में पुनः साहस पैदा करना चाहियें।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : हमें प्रतिरक्षा की स्थिति को भली प्रकार सभ-समझना चाहिये और पुरानी बात और वर्तमान बात को मिला नहीं देना चाहिये। हमारी सेना सक्षम है किन्तु शत्रु ने हमें धोखा दिया था।

प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो हम सीमा को पार भी करेंगे। किन्तु, कहा जाता है कि ऐसे आश्वासन प्रायः दिये जाते हैं और उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता वास्तव में आज स्थिति यह है कि हमें विदेशियों से सुनी बात पर विश्वास आता है। यदि वे कांगों में भारतीय जवान के कार्य की प्रशंसा करते है तो हम उस पर विश्वास करते हैं किन्तु हम यह नहीं मानते कि चुशूल में भारतीय सैनिकों ने कितना महान काम किया है। उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे और २०० या ३०० जवानों ने १८०० चीनियों को मार डाला था और अपने मोर्चे पर डटे रहे थे। अतः हमें जवानों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिये। वे तो कहते हैं:—

"We would fight with spirit and shed our blood to save our land."

तकनीशनों की भर्ती पर बहुत कम बल दिया जाता है। तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ानी चाहियें। गरीब किसान अधिकाधिक जन और धन प्रतिरक्षा के लिए दे रहे हैं किन्तु बड़ी बड़ी कम्पनियों वाले धनी क्या दे रहे हैं। वे केवल भाषणों द्वारा अपनी देश भक्ति प्रकट करते हैं।

हमारे सैनिक धन से खरीदे हुए सेवक नहीं बल्कि वे स्वयंसेवी हैं अन्यथा ६०-७० रुपये तो वेतन नहीं बल्कि मानदेय ही है। अतः हमें वायुसेना, नौसेना की शस्त्रास्त्र की कमी को पूरा करना चाहिये।

सैनिकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। भारतीय सैनिक अभियोग अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त नहीं हो पाते। मुरब्बा बंदी में उन्हें खराब भूमि दी जाती है। बाढ़ नियंत्रण में भी उनके परिवारों

को यह कह कर सहायता नहीं दी जाती कि उनके अभिभावक सरकारी नौकर हैं । नागरिक परिषदों से भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उन की अपेक्षा तो भूतपूर्व सैनिक बोर्ड ही अच्छे थे।

अहीरों में जिन्होंने चुशल की लड़ाई जीती थी यह असंतोष है कि उनकी अलग रेजीमेंट नहीं और उनकी सेवाओं को इस कारण मान्यता दी जा रही थी कि वे १८५७ में अंग्रजों के विरुद्ध लड़े थे।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : श्री चह्वाण ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रतिरक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार किया है और देश में प्रतिरक्षा की चेतना जगा रहे हैं।

आज हमें दो शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने यहां वचन दिया था कि हम शत्रुओं को अपनी भूमि से निकाल कर दम लेंगे । यदि कल हमला हो जाता है तो क्या हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? चीन भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकाधिक वैमनस्य पैदा कर रहा है। पाकिस्तान ने काश्मीर की समस्या को फिर से खड़ा कर दिया है और दूसरी पूर्वी बंगाल में उपद्रव आरम्भ कर दिये है। हमें देखना है कि यदि पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तब भी अमरीका और इंगलैंड उसी तरह हमारी सहायता करते हैं जिस तरह चीन के आक्रमण के समय किया था या नहीं । हमारा प्रचार निर्बल है। हम सभ्य देशों को यह नहीं बता सके कि पाकिस्तान काश्मीर में आक्रान्ता है, जबकि पाकिस्तान के समर्थकों की संख्या बढ़ गई है।

अत: मेरा निवेदन यह है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय को पूर्ण समन्वय से मिल-जुल कर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए कि प्रभावशाली प्रचार करके संसार को यह बताया जा सके कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान गलती कर रहा है. परन्तु हमें भी विदेशों से यथासम्भव सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें निश्चित रूप से यह पता लग जाना चाहिए कि हमें कितनी सहायता मिल जाने की सम्भावना है। हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमें आधुनिकतम और नवीनतम शस्त्र आवश्यक रूप से प्राप्त हो। हमें इस बात का भी पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि हमें तकनीकी व्यक्तियों की कमी न रहे हमें यह याद रखना चाहिए कि युद्ध एक दम से सामने आ सकता है अतः कोई कारण नहीं कि भर्ती के मामले में हम आत्मतुष्ट हो कर बैठ रहें। हमें हर दम तैयार रहना चाहिए।

यदि हमारे देश के सभी पक्ष संगठित होकर सरकार को समर्थन देने के लिए खड़े हो गये तो हमें सभ्यता संसार की सहानुभूति प्राप्त हो जायेगी । मुझे इस बात की पूर्ण आशा है कि हम अपना प्रण पूरा करेंगे और अपने क्षेत्रों से शत्रु को निकालने में सफल हो जायेंगे ।

श्री हेम राज (कांगड़ा): कल श्री रंगा ने कहा था कि पहाड़ी डिवीजनों में हिमालय के क्षेत्रों के लोगों को नहीं लिया गया है । मेरे विचार में वह भूल में थे । मेरे विचार में इस समय इन क्षेत्रों में सब से अधिक विकास का निर्माण हुआ है । कमाऊं डिवीज़न, डोगरा रैजीमेंट, गढ़वाल रैजीमेन्ट और गोरखा रैजीमेंट इन सब में हिमालय क्षेत्र के लोग ही

तो हैं। परन्तु मेरे विचार में श्री रंगा चाहते हैं कि दक्षिण के लोगों को अधिक भर्ती किया जाय। हमें तो पहाड़ी डिवीजनों में काफी अच्छा प्रतिनिधित्व मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है और उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। यद्यपि इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। हमारी उत्तरी सीमा तथा पाकिस्तान के साथ लगती सीमा बड़ी लम्बी चौड़ी है। आज हमारे देश पर चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से आक्रमण का खतरा है अतः हमें अपने सशस्त्र बलों को शक्तिशाली बनाना है। हमें किसी भी हालत में भर्ती के प्रति उदासीनता नहीं होना है, तथा आलस्य नहीं दिखाना है। चीन ने तिब्बत में १३ डिवीजन सेना रखी है जिन में १३ को सीमान्त पर रखा गया है। और केवल छः डिवीजनों का ही निर्मात किया है। मेरे विचार में यह पर्याप्त नहीं है। यह संख्या कम से कम १२ होनी चाहिए।

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही ओर से हमारे क्षेत्र में छापे मारे जा रहे हैं। और ये छापे अथवा आक्रमण प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि सारे के सारे सीमा क्षेत्र पर से पाकिस्तानी और चीनी तत्वों को बाहर निकालने का पूरा प्रयत्न करना है। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति भी हमें जागरूक होना है जो कि देश में गड़बड़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन राष्ट्रविरोधी तत्वों को निकालने से जो स्थान खाली हों वहां इन क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाय। मेरे विचार में इस से हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी सीमा तक सुरक्षा की व्यवस्था हो जायेगी। और अब जब कि आपात काल के कारण सरकार के पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं तो उन्हें इस काम को कर ही लेना चाहिये। इसी तरह पर्वतीय डिवीजनों की स्थापना भी शीघ्र ही कर देनी चाहिए और यह स्थापना आपातकालीन आधार पर होनी चाहिए।

'एवरो ७४८' के निर्माण का कार्य भी तेज होना चाहिए। परिवहन विमान सैनिकों की सुरक्षा तथा संभरण मार्ग की सुरक्षा के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे। और मेरा विचार है कि इस तरह के विमान हमारे पास काफी संख्या में होने चाहिए। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि जे० सी० ओ० की स्थिति को सुधारा जाय। इन लोगों को कुछ अधिक पदोन्नतियां मिलनी चाहिए। पहिले १० प्रतिशत थी परन्तु अब २४ प्रतिशत कर दी गयी है चीनी आक्रमण में इन लोगों ने काफी आक्रमण के दृश्य दिखाये हैं। मेरे विचार में इन के लिए कमीशन में ४० प्रतिशत व्यवस्था कर दी जानी चाहिये।

६ युद्ध का सामान बनाने वाले कारखाने हैं, परन्तु केवल दो एसे हैं जो पूरी तरह काम कर रहे हैं क्या शस्त्र अस्त्रों में आत्मनिर्भर होने की कोई लक्ष्य तिथि मंत्री महोदय बता सकते हैं मेरा यह भी निवेदन है कि सीमान्त सड़क विभाग को परिवहन मंत्रालय से निकाल कर प्रतिरक्षा मंत्रालय के सपुर्द कर देना चाहिए। निर्योग्यता वेतन वृत्ति का सम्बन्ध है यह कुछ रोगों में ही दी जाती है यदि २० प्रतिशत रोग युद्ध सेवा के साथ ही सम्बन्धित हो तो स्थिति क्या हो सकती है। मेरे विचार जो भी व्यक्ति सेवा में अयोग्य हो जाये उसे पेन्शन मिलनी चाहिए। ये केवल कुछ ही रोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिये। सभी सेनाओं में कल्याण अधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। पंजाब में काफी भर्ती हो रही है वहां तो कल्याण अधिकारी नियुक्त किये ही जाने चाहिए।

डोगरा लोग काफी बीर जाति के हैं। हाल ही के चीनी आक्रमण में उन्होंने काफी बीरता दिखाई है। डोगरा क्षेत्र में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है। इस क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोला जाना चाहिए। भूतपूर्व आजाद हिन्द सेना के लोगों के लिए १ करोड़ दिया जाना चाहिये। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि युद्धोत्तर पुर्निमाण कोष को स्थायी बनाना चाहिए। डोगरा लोगों को डाक्टरी सेवा के लिए भी भर्ती किया जाना चाहिये। देहरादून अकादमी में डोगरों का चिह्न भी रखना चाहिए। मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री म० ला० जाधव (मालेगांव): मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। भारत एक शांतिप्रिय देश है। आज हमारे देश पर चीन और पाकिस्तान दोनों का आक्रमण कर रहे हैं। हमें उन आक्रमणों का उत्तर देना है और अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है। नेफा की लड़ाई में हमें हारों का मुह देखना पड़ा था। मेरा निवेदन है कि यह बड़ा ही आवश्यक है कि चीनी आक्रमण के समय "नेफा" में जो हमें हारें हुई उसके सम्बन्ध में हुई जांच के प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिए। इस पर विचार करने से हमें अपने दोषों को दूर करने का अवसर मिलेगा और हम अपनी सेनाओं का संगठन ठीक ढंग से कर सकेंगे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

हमारी सेनायें काफी मजबूत हैं परन्तु उन्हें आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिये जाने चाहियें। युद्ध की सामग्री अब कारखानों में तैयार हो रही है और भर्ती का कार्य भी अच्छी प्रकार से चल रहा है। नेफा में हार के कारण गुप्तचर सेना का अभाव भी था। अतः हमें उचित स्तर पर गुप्तचर सेवाओं को संगठित करने की बात पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रतिरक्षा उत्पादन की ओर तो ध्यान जाना ही चाहिए जिससे इस मामले में हम आत्म निर्भर हो सकें। हमें विदेशियों की सहायता पर सदा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस से विकास और प्रतिरक्षा के कार्य साथ साथ चल सकेंगे।

हमने देखा है कि हमारी बजट की मांगें बढ़ती चली जा रही हैं। १९६०–६१ में यह २८२ करोड़ रुपये थी। १९६१–६२ में यह ३१७ करोड़ रुपये हो गयी। १९६२–६३ में यह ३८० करोड़ रुपये की मांग थी परन्तु वास्तव में यह राशि ४७८ करोड़ थी। १९६३–६४ में ८७३ करोड़ हो गयी। यह इसलिए कि हमने चीन के हमले से अपनी रक्षा करनी थी। इस दिशा में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सीमावर्ती क्षेत्रों में लोक सहायक सेना शिविरों की बड़े पैमाने पर स्थापना की जानी चाहिये। इसके आधार पर वहां के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण, दिया जा सकेगा। इसके साथ ही मेरा यह भी विचार है कि सहायक सेना छात्र दल को समाप्त कर देना चाहिए। और उसे राष्ट्रीय सेना छात्र दल में विलीन कर दिया जाना चाहिए। और इसे सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में मेरा निवेदन है कि नासिक के मिग विमानों के कारखाने की प्रगति बड़ी धीमी है। सरकार की ओर से यह बताया जाना चाहिये कि प्रस्तावित मिग विमानों का उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा। इसी तरह मेरा यह भी विचार है कि भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाओं के कारणों की समुचित जांच होनी चाहिए। और उन के कारणों का पूर्ण रूप से अध्ययन करके उन के उपचार के उपाय करने चाहिऐ। सैनिकों, नाविकों, और वैमानिकों के बोर्डों को अधिक कुशलता और दक्षता से कार्य करना चाहिये।

जवानों को इन कार्यों से यह अनुभव होना चाहिए कि उनका भविष्य उनके हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। इन बोर्डों में केवल कागजी काम ही नहीं किया जाना चाहिये।

सैनिक स्कूलों के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में सैनिक स्कूल खोले जाने चाहिए। गरीब विद्यार्थियों को भी इसमें योग्यता के आधार पर दाखिला मिलना चाहिए। केवल सम्पन्न अभिभावकों के बच्चों को ही इन स्कूलों में नहीं लिया जाना चाहिए। इन शब्दों से मैं अनुदान सम्बन्धी मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अ० व० राघवन : (बडागरा) : हिमाचल की ऊंची चोटियों तथा पहाड़ों शिविरों पर हमारे वीर सैनिक पूर्ण जागरूकता से सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। भारी संकट और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी पुरातन वीर परम्पराओं पर पूरे उतर रहे हैं। एक भूत-पूर्व सैनिक के रूप में मेरा मन श्रद्धा से झुक जाता है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं।

मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि पुलिस की रिपोर्टों के आधार पर केरल में बहुत से नवयुवकों के सैनिक जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, बहुत से मामलों में ये रिपोर्ट ठीक नहीं होती और सैनिक जीवन में प्रवेश पाने के अभिलाषी नवयुवकों को इनके कारण अनावश्यक निराशा और परेशानी का मुख देखना पड़ता है। जब कभी किसी मामले में पुलिस की खराब रिपोर्ट आये तो उस मामले को राज्यों के सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिये। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशनें बहुत ही कम हैं, सरकार को यह देखना चाहिये कि सेवा के दौरान उनको दिये गये भत्ते भी पेंशन का हिसाब लगाते समय सम्मिलित किये जायें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जवानों को परिवारों वाले क्वार्टर दिये जाने चाहियें जिससे कि वे बहुत अधिक समय तक अपने परिवारों में पृथक न रहें। जवानों के लिये पदोन्नति के और अधिक मार्गों की व्यवस्था की जानी चाहिये। पदोन्नति के मामले में पुरुष नर्सों के साथ भेदभाव की नीति नहीं बरती जानी चाहिये, महिला नर्सों की भांति ही उन्हें भी स्वयंमेव ही अधिकारियों की श्रेणी पर पदोन्नति पाने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

केरल में भी कुछ प्रतिरक्षा उत्पादन स्थापित किये जाने चाहियें, उन एककों को क्षेत्रवार विभक्त कर दिया जाना चाहिये। अन्य श्रेणियों के लोगों के प्रतिनिधियों को भी सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों में स्थान दिया जाना चाहिये। स्थायी नियमित कमीशन की वार्षिक रिक्त स्थानों में अन्य पदों के लिए कोटा बढ़ा कर ५० प्रतिशत किया जाना चाहिए। आयु बढ़ा कर ३५ वर्ष कर देनी चाहिये। इसके बजाय कि सामान्य सैनिक 'दरबार' होंगे, सैनिक कल्याण अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहियें जो कि जवानों की कठिनाइयों को सुनें और उन्हें दूर करें। सामूहिक दृष्टि से देखने पर तो यही पता चलता है कि निराश होने की कोई बात नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न दिशाओं में हम काफी आगे बढ़े हैं। हमारी सेनाओं का विस्तार हो रहा है। प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ रहा है। हमें केवल जवानों की भावनाओं का ध्यान रखना है। उन्हें कुछ और अधिक दे दिया जाय तो किसी को भी कोई मलाल नहीं होगा। बल्कि मंत्री महोदय उन जवानों के लिए कुछ करेंगे तो सारे देश का समर्थन उनको प्राप्त होगा।

श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह (राजनन्द गांव) : प्रचार प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। प्रतिरक्षा के लिए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। परन्तु खेद की बात है कि इस दिशा में अपेक्षित पग नहीं उठाये जाते। हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिये प्रचार और अधिक अच्छी प्रकार सुव्यवस्थित होना चाहिये। देश में होने वाली भरती में सुधार करने का केवल मात्र मार्ग यही है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि एस० एस० ए० बोर्डस भतपूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देख भाल रखे। सरकार को यह देखना चाहिये कि भूतपूर्व सैनिकों को अपनी पेंशन नियमित रूप से बगैर किसी परेशानी के मिल जाये। बोर्डों में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये, इस प्रकार वे भावी रंगरूटों के लिये सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। भरती राज्यों के आधार पर की जानी चाहिये, अंशों के आधार पर नहीं।

सरकार को यह देखना चाहिये कि खेल-कूद आदि जैसे सभी कार्यकलापों की व्यवस्था राष्ट्रीय सेना छात्र दल के माध्यम से करवायी जाये। इससे यह अधिक लोकप्रिय होगा। अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रादेशिक सेना को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिये, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक सेना की अधिक बटालियन बनाई जानी चाहिये। रीवा और ग्वालियर जैसे प्राचीन भरती केन्द्रों को पुनरूज्जीवित कर दिया जाना चाहिये। आवश्यकता के समय असैनिक प्राधिकार की सहायता करने के लिये प्रादेशिक सेना का उपयोग किया जाना चाहिये। हमें अपनी नौसेना को और मजबूत बनाना चाहिये। कुछ पनडुब्बियों को प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाने चाहियें।

सरकार को यह देखना चाहिये कि मिग विमानों का उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ हो जाये, विमानों के ढांचों के एक स्थान पर बनाये जाने और जोड़ने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थान पर बनाये जाने के बारे में इस समय जो अस्तव्यवस्तता है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। कलाकारों संगीतज्ञों की भांति सशस्त्र सेनाओं के तिनिधियों को भी राज्य सभा में लिया जाना चाहिये, सशस्त्र सेना के कुछ व्यक्ति राज्य सभा में नाम निर्देशित कर दिये जाने चाहियें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : After attanining independence our Army has not been acting under the guidance of British Officers and commanders, but the skeleton still remains. The old traditions are still being followed. As an instance, I will refer to the "Beating of the Retreat" ceremony, on the occasion of the Independence Day Celebrations. At that occasion, I saw that the Church bells rang and Christian song "Abide with me O Lrord" was played. I believe that the political thinkers are mainly responsible for continuing such traditions. No steps have yet been taken to remove such anomalies.

One can associate today's situation with the situation prevalent thousand years back in one respect. It was said that our army was defeated because the elephant of Anangpal ran away from the battlefield. Similarly, today it has been said that our army has been defeated on the Northern borders because they were few in number, that we had not got modern weapons or that we had to fight at a very high altitude and so on. My submission is that these are not the causes but symptoms. This is a superficial view of the situation. Therefore, we should diagnose the disease properly. A very wide publicity

was given to the contributions made in the shape of ornaments, but such paltry contributions can hardly help solve the problem.

It is imperative that we change our way of looking at things. Shri Saraf was a little vexed at my reference to worship as absurd. In fact, I did not condemn worship as such. I only wanted to emphasize that worship will not help with a war or increase production.

I will refer to another historical instance. Tamur came here. He had heard much about the ferocious elephants of our armies. He had engineers and intelligence people with him who obtained every kind of information from our armies. When battle started his army spread out iron felters which made our elephants useless. This led to the defeat of our army then. Similarly, I found in the hilly areas that Chinese had effective intelligence sources. whereas our intelligence work is carried on through sherpa coolies. Our sources are most ineffective and insatisfactory. It seems that we are not prepared to learn anything from the development made by other countries in every field due to our false pride in our civilization and culture. This false pride is in fact responsible for our defeat.

An enquiry should be held, by this House, into the organisational methods of our Army since 1947. Whatever body is entrusted with this work, should also suggest appropriate modifications that ought to be made in it.

Today we don't find any link between our foreign policy and defence policy. Our policies are not based on realism. There is enough talk of vacating the aggression. Sometime some body says that China will not be allowed to repeat the past history and another time it is said that even our inch of territory in Kashmir will not be handed over to Pakistan. But this loud talk and tall talk will not carry us anywhere. Our policies should be based on realism and there should be harmony among the various organs of the state. There is no use talking about such things as somebody said, that Pakistan had a hand behind Poonch explosion Somebody says that we will cross the cease-fire line. Another person says that we should purchase atomic weapons as if atomic weapons are being sold in the market place. In all such, after taking a realistic view of the matters, we have to act in accordance with the situation, and not merely talk loudly.

In our foreign policy as well as in defence policy, we should expect any kind of help only from those countries which are really capable of giving help. It is wrong to depend totally on America, Britain or Russia, for help. We should strengthen ourselves and welcome help from all quaters as and when occasion arises. We have pursued a policy for the last 17 years, which will not work in future. Henceforth our policy should be based on some firm principle, because times have now changed.

I want to know the proportion of Brigadiers promoted from the rank of soldiers and Lieutenants, respectively. 75 percent Brigadiers should be promoted from among the soldiers and 25 per cent from Lieutenants. Rifle training should be given to larger number of people in the country.

Injured soldiers should be given compensation. There should not be wide disparity in the uniform allowance being given to soldiers and officers. Also, there should not be so much difference in rations being given to soldiers and officers, who are there on the front line. Less amounts should be spent on the quarters for the officers. The Government should take upon itself

the responsibility of educating the children of these armymen who died in harness. The Director in the Research Directorate of the Army should be appointed immediately. The contributions, made for Army in Schools and Colleges, are not passed on till the Minister goes there personally. This kind of practice should be stopped. The allowance, that is given to children of the N.C.C., is not being paid in certain cases.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव): मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं जिन्होंने चीनियों को साथ लड़ते हुये अथवा पाकिस्तानी सिपाहियों के फलस्वरूप अपने प्राण दिये।

पेंशन आदि द्वारा उन्हें दी जाने वाली सुविधायें, जो प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं, अत्यंत अल्प हैं। इस सम्बन्ध में इस समय लागू नियमों का निरीक्षण किया जाये।

मैं प्रतिवेदन का भी स्वागत करता हूं। इस आश्वासन का भी स्वागत करता हूं कि पिछले आक्रमण के समय हुई गलतियां अब नहीं होंगी। पाकिस्तान और चीन में समझौता होने से स्थिति और भी नाजुक हो गई है। इसका सामना करने का हर संभव उपाय किया जाये।

काश्मीर के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय की सलाह ले कर सुरक्षा परिषद को कहे कि यदि एक उल्लिखित समय में पाकिस्तान ने युद्धविराम रेखा का पालन नहीं किया तो हम खोया हुआ प्रदेश वापिस लेने के लिये सशस्त्र कार्यवाही करेंगे।

पूर्वी क्षेत्र में हमें पहले केवल उत्तर की ओर से ही खतरा था किन्तु अब उत्तर और पूर्वी दोनों ओर से खतरा है। पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश को रोका जाना चाहिये। इस बात की भी जांच की जानी चाहिये कि ये विद्रोही नागाओं के समान क्या यह भी हथियार साथ लेकर आये हैं।

हमारे सामने नागा विद्रोहियों की समस्या भी है। ये लोग पूर्वी पाकिस्तान से हथियार प्राप्त करके आसाम की नागा पहाड़ियों तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में उपद्रव पैदा करते हैं। पूर्वी क्षेत्र में विद्रोही नागाओं की इस प्रकार की कार्यवाहियों को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय को एक साथ मिलकर कोई हल निकालना चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों का शीघ्र विकास किया जाना चाहिए। इस कार्य में विशेष रूप से परिवहन संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने के लिये सीमाओं पर सैन्य विनियोजन होना चाहिए।

पूर्वी क्षेत्र के लिये सुरक्षा की दृष्टि से एक पूर्णांग कमान नियुक्त की जानी चाहिए जिसका मुख्यालय ऐसे उपयुक्त स्थान पर हो जहां वायुयान द्वारा और सड़क, रेल तथा नदी मार्ग से भी पहुंचा जा सके।

पूर्वी पाकिस्तान से आसाम तथा अन्य स्थानों में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की बढ़ती हुई संख्या से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। यह संतोष की बात है कि इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिये गृह-कार्य मंत्री महोदय ने भरसक प्रयत्न

करने का आश्वासन दिया है। अवैध रूप से घुस आने वाले लोगों को देश से बाहर निकालना हमारी आन्तरिक सुरक्षा के हित में एक सक्रिय कदम होगा।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : यह सराहनीय बात है कि पुरानी परिपाटी को तोड़ कर पहली बार प्रतिरक्षा मंत्रालय के इस वर्ष के प्रतिवेदन में तथ्यों के बारे में कुछ प्रारम्भिक जानकारी दी गई है।

यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिरक्षा सेवाओं और राजनीतिज्ञों के बीच कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रहा है तथा राजनीतिज्ञों के पास प्रतिरक्षा के बारे में वास्तविक जानकारी का अभाव होने के कारण परामर्शदात्री समितियों जैसी समितियों में जितनी भी चर्चायें हुई हैं वे कभी भी अधिक अर्थपूर्ण नहीं रही हैं। आपातकाल के दौरान सरकार को एक प्रतिरक्षा संबंधी सस्थायी समिति नियुक्त करनी चाहिए थी। सदन को प्रतिरक्षा की दिशा में की जाने वाली कार्यवाहियों की पर्याप्त जानकारी दी जाने चाहिए जिससे सदस्यों को यह पता चल सके कि सरकार प्रतिरक्षा के लिये क्या कदम उठा रही है। यह दुख की बात है कि सरकारी मशीनरी फिर ढीली पड़ने लगी है। जनता में आपातकाल की भावना समाप्त हो गई है और उसमें आत्मतुष्टि की भावना आ गई है। देश के लिए अभी भी बाहरी खतरा बना हुआ है। हमें इसके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को हमारी तटस्थता की नीति के परिणामों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तथा यदि देश की सुरक्षा की दृष्टि से इसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन किये जाने चाहिएं। आज हम परमाणु युग से गुजर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो वस्तु आज आधुनिक है वह कल पुरानी हो जाती है और इस भ्रम में पड़े रहना खतरनाक है कि भारत प्रतिरक्षा के मामले में ३० या ५० वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आज कोई भी देश गुटों से अलग रह कर सुरक्षित नहीं रह सकता। हमें आज वास्तविकता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम बार बार गुटबन्दी से अलग रहने की नीति का नारा लगा कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर बना रहे हैं जिसके परिणाम हमारे लिये गम्भीर हो सकते हैं।

पाकिस्तान सीटो और सेन्टो का सदस्य होने के कारण सैनिक शक्ति में हम से अधिक शक्तिशाली है। उसके पास आधुनिकतम हथियार हैं। ब्रिटेन, अमेरिका तथा राष्ट्रमंडल के देश हमारे मित्र अवश्य हो सकते हैं किन्तु संकट के समय स्वभावतः हमारी तुलना में पाकिस्तान को अपने गुट में होने के नाते सहायता के मामलों में अधिमान देंगे। यह हम स्पष्टरूप से देख चुके हैं कि चीनी आक्रमण के समय भी हमें पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाई जाने के कारण आधुनिकत्तम हथियार तथा 'सुपरसोनिक' विमान नहीं मिल सके थे, जबकि पाकिस्तान को ये हथियार और विमान पहले से ही सहायता के रूप में प्राप्त हैं। सरकार को इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करके देश के हित में उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

नेफा जांच संबंधी समिति की उपपत्तियों के परिणामस्वरूप सैनिक संगठन में दोषों को दूर करने के निमित्त जो अनेक समितियां नियुक्त की गई हैं, उनसे वास्तविक पुनर्गठन के किसी प्रयास का आभास नहीं मिलता है। सैनिक संगठन में निम्न स्तर पर से लेकर उच्चत्तम स्तर तक दोष ही भरे हैं। इन्हें दूर करने के लिए अब भी पुरानी प्रणाली अपनाई जा रही है। संगठन में परिवर्तन का विरोध किया जाता है क्योंकि पुराने संगठनात्मक प्रतिरूप संस्था का रूप धारण कर लेते हैं और निहित स्वार्थ इसके

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

परिवर्तन के मार्ग में बाधक बन जाते हैं । सैनिक बल की स्वायत्तता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । प्रतिरक्षा संबंधी मंत्रि मण्डलीय समिति के गठन और कृत्यों के बारे में सरकार को जानकारी देनी चाहिए । सरकार को अधिक संख्या में समितियां नियुक्त करने के स्थान पर सैनिक संगठन में सुधार करने के लिये कोई अधिक प्रभावी कदम उठाना चाहिए ।

सेना के तीन विभागों में अधिक समन्वय होना चाहिए और उनकी स्वायत्तता का किसी प्रकार हनन नहीं किया जाना चाहिए । सेनाध्यक्षों की समिति में भी आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । सरकार को पुरानी पद्धति का त्याग करके आधुनिक पद्धति अपनानी चाहिए । सेनाध्यक्षों की समिति का सभापति सेना का ही कोई अधिकारी होना चाहिए । ऐसा करना देश की सुरक्षा की दृष्टि से अधिक हितकर होगा ।

अधिकांश राष्ट्रों की भांति यहां भी एक सैनिक परिषद् होनी चाहिए जिसमें सेनाध्यक्ष अन्य अपने मुख्य स्टाफ अधिकारियों के साथ कार्य करें । इससे संयुक्त निर्णय लेना संभव हो सकेगा जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से अधिक हितकर होगा ।

नेफा में जो विध्वंस हुआ, वहां पर स्थिति क्या थी । हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी दुर्बल और अक्षम थे । इसके लिये अब समय आ गया है कि एक सेना परिषद बनाई जाय जो संयुक्त रूप से कार्य करे ।

एक सैनिक आलोचक ने अपने लेख में बताया कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में दस गुना प्रयोगशालाएं हैं परन्तु उनमें जो गवेषणा कार्य होता है वह उनका दसवां भाग भी नहीं है : उसने कहा कि हमारे अनुसंधान संगठन में न तो उत्साह है और न संगठित प्रयत्न ही किये जाते हैं । संसार के बड़े बड़े देश भी अकेले ही अनुसंधान कार्य नहीं करते । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम अनुसंधान के सिलसिले में किसी का सहयोग प्राप्त करते हैं ?

हमने परमाणु हथियारों के विकास कार्य को न करने का निर्णय लिया है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यह नीति किस कारण बनाई गई है ? यदि हम परमाणु हथियारों का विकास नहीं करेंगे तो हमें भयंकर परिणामों का सामना करना होगा । चीन ने अणु गवेषणा संबंधी कार्यवाहियां तीव्र गति से आरम्भ कर दी हैं । वर्ष १९५५ में चीन ने, रूसी सहायता से, ३६ परमाणु अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिये थे और वर्ष १९५८ में पहला अणु रिएक्टर स्थापित कर लिया था और सुना है इस वर्ष वह पहला परमाणु परीक्षण भी करने जा रहे हैं । चीन आज छोटे शस्त्रास्त्रों में आत्म निर्भर है और वह टैंकों का निर्माण भी स्वयं कर रहा है । परन्तु हम अभी मध्यम श्रेणी के टैंक भी नहीं बना रहे हैं । चीन की नीति हमें एकलित करने की है और वह हो सका तो युद्ध द्वारा भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा ।

प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उत्पादन सम्बंन्धी कार्य भी सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है । इससे प्रतीत होता है कि हम अभी छोटे शस्त्रास्त्र के निर्माण की अवस्था में ही हैं । ७.६२ एम० एम० गोला बारूद तैयार करने में भी अभी कम से कम एक वर्ष लगेगा । १४ नवम्बर, १९६३ के "हिन्दुस्तान टाईम्स" की सूचना के अनुसार सरकार ईशापुर में केवल ५,००० सेमी-आटोमेटिक हथियार ही बना रही है, जो संख्या पर्याप्त नहीं है । हमारे मुकाबले में चीन की शस्त्रास्त्र संबंधी शक्ति बहुत अधिक है । शस्त्रास्त्रों का मुकाबला शारीरिक उत्साह आदि से नहीं किया जा सकता ।

हम कई प्रकार के विमान बना रहे हैं, जैसे ए एन-१२ नाट, कैरीबो, एवरो-७४८, एच एफ-२४ और मिग भी। परन्तु क्या इन विभिन्न प्रकार के विमानों के बारे में प्रशिक्षण और पुर्जों आदि की कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हो जायेंगी।

टाटा समिति ने सिफारिश की थी कि मिग और एवरो-७४८ परियोजनाओं को समाप्त कर दिया जाय। परन्तु चूंकि हम एवरो-७४८ परियोजना पर करोड़ों रुपये व्यय कर चुके थे इसलिये एक राजनीतिक निर्णय लेकर उस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि एच एफ-२४ के बारे में जो विवाद है उस में सच्चाई क्या है ? मैंने सुना है कि इसमें जो इंजन लगाया जायेगा उसकी गति बहुत कम होगी। आपने अगस्त, १९६२ में इस बारे में निर्णय लिया था और अब सरकार बता रही है कि वह कारखाने स्थापित करने जा रही है। आठ वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश सार्थ के साथ समझौता हुआ था और हमें यह भी मालूम नहीं कि पहला एच एफ-२४ कब तक तैयार होगा। इन बातों से पता चलता है कि सरकार प्रतिरक्षा के मामले में तत्पर नहीं है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हम हर तरह की सहायता सरकार को देने को तैयार हैं, परन्तु अब देश यह सहन नहीं करेगा कि नेफा जैसी स्थिति फिर पैदा हो। तटस्थता एवं शांति बनाये रखने की नीति, चाहे उसके लिये कितनी ही कीमत अदा करनी पड़े, संसार में आज मान्य नहीं है।

श्री कृष्णपाल सिंह (जालेसर) : श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह ने जो सुझाव दिया था कि दो या तीन वरिष्ठ सेना पदाधिकारियों को राज्य सभा के लिये नाम निर्दिष्ट किया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं।

जब युद्ध छिड़ा तो प्रतिरक्षा कार्यों पर राजस्व का ७२.६ प्रतिशत भाग व्यय किया गया और उसके साथ ब्रिटेन आदि देशों ने सहायता भी की। परन्तु इसके बावजूद भी हमारा व्यय कुल व्यय का २९.५ प्रतिशत ही है, जब कि अमरीका, जहां पर स्थिति सामान्य है, ४०.७७ प्रतिशत प्रतिरक्षा पर व्यय करता है। हमें प्रतिरक्षा कार्यों पर और अधिक व्यय करना चाहिए।

योजना विभाग में लगभग ५०,००० व्यक्ति काम करते हैं परन्तु यह विभाग कोई विशेष काम नहीं कर रहा है। इस विभाग का काम अन्य विभागों द्वारा किया जा सकता है और इन ५०,००० व्यक्तियों का प्रयोग सशस्त्र सेना के काम के लिये किया जा सकता है।

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के आने से उत्तेजना बढ़ रही है। इसी प्रकार की समस्या चैकोस्लोवाकिया में भी उत्पन्न हो गयी थी और बाद में उसका विभाजन हुआ था। परन्तु इस प्रकार का सुझाव नहीं रख सकते चूंकि हम पूरी तरह से सशक्त नहीं हैं।

हमें विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों एवं विमानों का निर्माण करने की बजाय एक प्रकार के विमान के निर्माण पर बल देना चाहिए, ताकि पुर्जों और प्रशिक्षण संबंधी कठिनाइयां हमारे समक्ष न आयें।

पर्वतीय (माउंटेन) डिवीजन तैयार करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं, परन्तु पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण और काफी ऊंचाई पर रहने की आदत केवल इन डिवीजनों के सैनिकों को ही नहीं डालनी चाहिए। यह पहाड़ी डिवीजन केवल पहाड़ों के लिये ही नहीं बनाये जाने चाहिएं। अन्य सैनिकों को पहाड़ी में रहने की आदत डालनी चाहिए और इसी प्रकार पहाड़ी डिवीजनों को मैदानी क्षेत्रों में लड़ने आदि का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

सैनिकों के साथ व्यवहार अधिक सम्मान पूर्वक होना चाहिए । और जो सैनिक गुम हैं उन के बारे में उनके परिवारों को अविलम्ब सूचना देनी चाहिए । यदि हम उन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते तो रेड क्रास की सहायता प्राप्त करके यह काम करना चाहिए । सेना में केवल वही लोग भर्ती करने चाहिएं जो सबल हैं और साहसी भी हैं । केवल भत्तों और वेतनों के इच्छुक लोगों को भर्ती नहीं करना चाहिए । सेना में पदोन्नति की पद्धति असन्तोषजनक है । पदोन्नति के सिलसिले में पक्षपात नहीं बरता जाना चाहिए ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसोर) : प्रतिवेदनों से विदित है कि फिजूलखर्ची किस तरह बढ़ रही है । जे सी ओस के लिये एक साथ क्वार्टर न बनाने पर काफी हानि हुई । एक स्थान पर १४०० टन सीमेंट का गबन हुआ । राशन की चोरी से ५ लाख का घाटा हुआ । हमने देखा है कि किस प्रकार वायु बल की ८ करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक थी । दो स्थानों पर विमानों को हुई क्षति के कारण क्रमशः २४,००० और ४२,००० रुपये का घाटा हुआ जिस के कारण सम्बद्ध अधिकारियों से १५० और २०० रुपये क्रमशः वसूल किये गये । अधिकारियों से इतनी राशि का जुर्माने के तौर पर वसूल करना अनुचित बात है ।

हमने देखा है कि एक स्थान पर १६६६ मोटर गाडियां बेकार हो गईं और एक अन्य स्थान पर ७७६ गाड़ियां बेकार हुईं । इन गाड़ियों को यदि समय पर बेच दिया जाता तो यह हानि न होती । इस कारण १ करोड़ रुपये की क्षति हुई ।

इसके अतिरिक्त कैंटीन स्टोर विभाग संबंधी कोई मांग नहीं दिखाई गई । इस विभाग का भाण्डागारों में २ करोड़ रुपये का सामान है । यह सामान कहां से आया । मैं पूछना चाहता हूं कि इस विभाग का उल्लेख जब मंत्रालय के प्राक्कलनों में नहीं पाया जाता तो मंत्री महोदय ने इस के लेखों पर कैसे हस्ताक्षर कर दिये ? जो ५६ लाख रुपये का लाभ हुआ है उस पर आय-कर क्यों नहीं लगा ? न तो यह एक उपक्रम ही है और परिनियत निकाय ही । यह विभाग लाखों रुपये के सामान कैसे खरीदता है ?

निश्चय ही हमारे सैनिक बल काफी सुदृढ़ हुए हैं परन्तु अभी इन्हें और सुदृढ़ बनाना वांछनीय है । हमारी सेना को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह शत्रुओं का मुकाबला करने योग्य हो जाय ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) I have full faith in the character and patriotism of four present Defence Minister. Had he been made our Defence Minister seven or eight years back, we would not have to face the present situation. Now he will have to prepare the nation all over again. Defence problem can be solved neither by the Government alone nor by the Army. To solve this problem we will have to prepare the whole nation. The method of training will have to be changed altogether.

The fear of war has to be eliminated. This is a wrong impression that nations perish by warfare. Germany, which was a centre of bloodshed once, is now in a position to give us loans. The communities and races which are martial in character usually are vanguishers and successful.

Patriotism and fear of God are the two essentials which can help build the nation on stronger footings. It is really deplorable that these two qualities are lacking today. Instead, today we have man worship. When China attacked us, the country was asked to srrengthen the hands of Mr. Nehru. It was due to such a wrong approach that China was able to grab our territories. It is Mr. Nehru who is responsible for the NEFA Debacle. His policy is weak.

Yet the country was asked to strengthen his hands. Such man worship ought to be got rid of. We will have to prepare the whole nation to face the external threats. We will have to change our way of thinking.

The All India Radio can help prepare the nation, but its programmes today are wholly unsatisfactory and misguided.

We will have to accelerate the speed of strengthening the nation. We need 1794 engineers in the army, but so far only 145 people have been recruited That demonstrates that we are moving at a snail's pace. Arms Act was enacted. by the Britishers and it is wholly antagonistic to our nation's welfare. Even Mcmahon Line was a creation of Britishers and we must deny this Mcmahon Line if we want to save our country. Colombo Proposals also cannot help us. It is a fight between two lions and petty foxes are trying to bring them around. If we want to exist, the only way is to strengthen our country, to prepare our masses for the defence of our country.

The land suitable for the cultivation of wheat has gone to Pakistan. Except 5 per cent people of Pakistan, who have vested interests, all the other 95 per cent people are in favour of reunion with India. Our food problem can be solved only if we try to reunite Pakistan with India. Our defence problem can also be solved if there is re-union of India and Pakistan. We must create an atmosphere for such a reunion. Our heads hang in shame when we hear that Pakistanis committed 615 rapes on our mothers and sisters.

The Government is committed to the safety and defence of 40 crores of people. It must prepare the nation and fulfil its responsibility.

श्री शिकरे : (मरमागोआ) : मुझे भी अवसर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी एक दल से सम्बद्ध नहीं हैं। एक असम्बद्ध सदस्य को मैंने अवसर दे दिया है। मैं वित्त विधेयक पर चर्चा के समय आप को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : माननीय सदस्य ने एक असांसदीय टिप्पण किया 'उन्होंने कहा कि :

It is a fight between two lions and petty foxes are trying to bring them around.

Mr. Speaker : This expression is not unparliamentary. But it should not be used, especially in regard to any other country.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जिस रचनात्मक ढंग से प्रतिरक्षा संबंधी अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई उसके लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सोमवार अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, २३ मार्च, १९६४/चैत्र ३, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, March 23, 1964/Chaitra 3, 1886 (Saka).